(c) the steps taken or proposed to be taken to seek cooperation from the countries where wildlife products are sold openly;

(d) whether Government also propose to amend the Wildlife Protection Act to deal more effectively with the wildlife and forest-related crimes; and

(e) if so, the detials thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABU LAL MARANDI): (a) and (b) A special inter ministerial coordination and enforcement committee for strengthening measures for control of poaching and illegal trade in wildlife comprising of members from Ministry of Environment & Forests, Ministry of Home Affairs and Ministry of Finance has been constituted.

(c) International trade in wildlife and wildlife products are regulated under the provisions of Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora (CITES). About 140 countries are member of CITES. India is also one of the member and regularly monitors the international trade in wild animals.

A transboundary meeting was held between India and Nepal in Kathmandu in 1997 to look into the issues of illegal trade of wildlife parts and products across Indo-Nepal Border.

(d) and (e) Yes Sir. The Government has proposed to enhance the penalties and make it more stringent.

Increasing incidents of poaching

2193. SHRI PREM CHAND GUPTA:
DR. B.B. DUTTA:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recently some film actors were caught shooting endangered species of Deer in Rajasthan in violation of the Wildlife Conservation Act, 1972;

(b) whether poaching for sport or commercial purposes is rampant and posing a serious threat to our wildlife, especially protected species like Tiger, Leopard, Elephants, Rhino etc.

(c) whether the present security arrangements by the Forest Department are ineffective; and

(d) what action Government are taking in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABU LAL MARANDI): (a) Yes, Sir.

(b) Instances of poaching for sport & commercial purposes come to the notice of the Government from time to time.

(c) As the economic benefits of poaching and illegal trade in wild animal and products increase, there is a greater need for strengthening the enforcement infrastructure including availability of better equipment and improved communication.

(d) Central Government provides assistance to the State Governments for purchase of vehicles, fire arms and erection of wireless network. Training programmes on techniques of detection and investigation have also been organised

सौराष्ट्र में औद्योगिक एककों द्वारा पेयजल तथा कृषि भूमि को प्रदूषित किया जाना

2119. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में पेयजल और कृषि भूमि को वहां स्थापित औद्योगिक एककों द्वारा प्रदूषित किए जाने की जानकारी है और यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस दिशा में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसमें संलिप्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मंत्रालय स्तर पर क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के कुछ भागों में औद्योगिक एककों से प्रवाहित होने वाले बहिस्रावों द्वारा पेयजल की गुणवत्ता और कृषि भूमि खराब होने के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें प्रमुख रूप से जैतपुर क्षेत्र में तथा उसके आसपास लघु रंगाई और छपाई एककों द्वारा प्रवाहित होने वाले बहिस्रावों के कारण प्राप्त हुई हैं। जैतपुर में एक साझा बहिस्राव शोधन संयत्र का समुन्नयन किया गया है जिसे जून, 1998 में पूरा किया गया है। इस क्षेत्र के प्रदूषण फैलाने वाले साड़ी छपाई एककों के बहिस्राव को उठाकर साझा बहिस्राव शोधन संयत्र (सीईटीपी) में संसाधित किया जाता है।

सारीगम औद्योगिक क्षेत्र में तथा उसके आसपास रसायन उद्योगों से प्रवाहित होने वाले अपशिष्ट जल के कारण वलसाड जिले के सारीगम क्षेत्र से कृषि भूमि अवक्रमण (डिग्रेडेशन) की शिकायतें भी मिली हैं। इस क्षेत्र में बहिस्रावों के निपटान के लिए एक सी ई टी पी और साझा पाइप लाइन है। इस क्षेत्र के एककों के पास पहले उपयुक्त संसाधन (ट्रीटमैंट) सुविधाएं नहीं थीं और उनके द्वारा आंशिक रूप से संसाधित बहिस्रावों को समीपस्थ नाले में प्रवाहित कर दिया जाता था। सी ई टी पी को अब चालू कर दिया गया है और ज्वारनदमुखी क्षेत्र में संसाधित बहिस्राव प्रवाहित करने के लिए भूमिगत (अंडरग्राउंड) पाइपलाइन को पूरा किया गया है।

(ग) सरकार ने इस क्षेत्र में जागरूकता उत्पन्न की है और प्रदूषण फैलाने वाले एककों को सी॰ई॰टी॰पी॰ के सदस्य बनने के लिए राजी किया है।

(घ) गुजरात उच्च न्यायालय ने यह मामला अपने हाथ में ले लिया है और दोषी एककों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की गई। दोषी एककों को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा बन्द कर दिया गया। यह मामला न्यायालय में लम्बित है।

Dwindling tiger population in Orissa

2195. SHRI AKHILESH DAS:

SHRI BHAGABAN MAJHI:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether as reported in the Indian Express, New Delhi edition of 12th August, 1998, the tiger population in Orissa is fast dwindling;

(b) if so, the comparative figures of tiger population in Orissa forests and other reserves and sanctuaries as per periodical census since 1980 onwards; and

(c) the steps taken to preserve and promote the tiger population in different reserves?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARANDI): (a) and (b) There has been a decline in tiger population of Orissa after 1989. The details of estimated tiger population in the State since 1980 as reported by the State Government is as under:

Year	1984	1989	1993	1997
Tiger population	202	243	226	194

The figures of tiger populations as per the past successive estimations carried out in the country and Tiger Reserves are given separately in statement. I and II (*See* below)

(c) The various measures taken by the Government to conserve the tiger population are enlisted in statement III.